



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1546]
No. 1546]नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2007/अग्रहायण 23, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2007/AGRAHAYANA 23, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2132(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 फ प (वी यू) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XII -छ के अनुसार टनभार कर-प्रणाली अपनाना चुनने वाली नौवहन कंपनियों द्वारा प्रशिक्षण सुलभ करवाए जाने के बारे में दिनांक 30.12.2004 की अधिसूचना सं 0 का 03A0 1436 (अ) द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत पहले जारी किए थे। केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत अधिसूचित करती है :-

1. टनभार कर चुनने वाली कंपनी सभी जहाजों पर अथवा अपने किसी भी अर्हकारी जहाज पर प्रशिक्षणार्थी अधिकारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण से संबंधित कार्य के कुल दिन, न्यूनतम प्रशिक्षण से संबंधित अपेक्षा पूरी करने की दृष्टि से आवश्यक प्रशिक्षण के कार्य के दिनों से कम नहीं हों।

स्पष्टीकरण : इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रयोजन के लिए ।

(क) प्रशिक्षणार्थी अधिकारी का अभिग्राय एक कैडिट जो नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित पूर्व समुद्री प्रशिक्षण पास कर चुका है तथा वह नौवहन-महानिदेशक द्वारा प्रकाशित समुद्री-शिक्षण और प्रशिक्षण-आकलन के बारे में नियम-पुस्तक में विनिर्दिष्ट अथवा नौवहन-महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुद्र में चल रहे जहाज पर प्रशिक्षणार्थी अधिकारी के रूप में तैनात होने वाला अपेक्षित अर्हताएँ रखने वाला व्यक्ति है।

(ख) "न्यास" का अभिप्राय, भारतीय राष्ट्रीय पोत-स्वामी-संघ के परामर्श से, नौवहन-महानिदेशालय द्वारा स्थापित समुद्री प्रशिक्षण न्यास है।

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यकता निम्नानुसार होगी :

(i) टनभार कर चुननेवाली कंपनी के अपने ही जहाज अथवा चार्टर किए गए जहाज (स्पेस अथवा

स्लॉट चार्टरों को छोड़कर) के मामले में प्रशिक्षण से संबंधित कार्य के दिनों की संख्या, किसी वित्तीय वर्ष में टनभार-कर चुनने वाली कंपनी द्वारा ऐसे जहाज चलाए जाने के दिनों को न्यूनतम सुरक्षा-जन-प्रबंध-दस्तावेज के अनुसार अथवा उसके यथानुपात में प्रत्येक दस (10) अनुपूरक के संबंध में एक और आधा (1.5) प्रशिक्षणार्थी अधिकारी के आधार पर, अपेक्षित प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों की संख्या से गुणा करने पर आने वाली संख्या के बराबर होगी।

(ii) स्पेस चार्टरों अथवा स्लॉट चार्टरों के मामले में, कार्य के दिनों की संख्या, टनभार-कर चुनने वाली कंपनी के स्लॉट/स्पेस चार्टरों के निवल टनभार में निवल टनभार गुणनखंड (फैक्टर) का भाग देकर और उससे आने वाली संख्या को टनभार चुनने वाली कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान जहाजों को चलाए जाने के दिनों की संख्या से गुणा करके एवं खंड 12 के अनुसार उस वित्त वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में रही, आगे लायी गयी कमी को शामिल करके परिकलित की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1: इस खंड के प्रयोजन से, स्लॉट/स्पेस चार्टरों का निवल टनभार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 फ छ (वी जी) के बारे में स्पष्टीकरण के संबंध में राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार यथा परिकलित निवल टनभार होगा।

स्पष्टीकरण 2 : निवल टनभार गुणनखंड (फैक्टर), नौवहन-महानिदेशालय द्वारा, वाणिज्यिक-पोत-परिवहन-अधिनियम, 1958 के अनुसार पंजीकृत सभी अर्हकारी जहाजों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष का, पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल निवल टनभार के रूप में परिकलित, अधिसूचित किया गया गुणनखंड (फैक्टर) होगा, जिसमें पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऐसे जहाजों की कुल संख्या का भाग दिया जाएगा और उसे नौवहन-महानिदेशक द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ होने के 60 दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाएगा।

(घ) "भारतीय राष्ट्रीय पोत-स्वामी-संघ" का अभिप्राय, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार पंजीकृत भारतीय पोत-स्वामी-संघ है।

(ङ.) "वित्तीय वर्ष" का अभिप्राय, 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि से है।

2. (क) टनभार कर चुनने वाली कंपनी समुद्र में चल रहे सभी जहाजों अथवा अपने किसी अर्हकारी जहाज पर अपने निजी संसाधनों से प्रशिक्षणार्थी अधिकारी भर्ती करेगी और समुद्री शिक्षण और

प्रशिक्षण आकलन के बारे में नियम पुस्तक एवं अथवा नौवहन-महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को प्रशिक्षण सुलभ करवाएगी।

(ख) टनभार कर चुनने वाली कंपनी अपने स्वयं के जलयानों के प्रकार अथवा इसकी व्यापारिक पद्धति अथवा नौवहन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट और अनुमोदित किए जाने वाले अन्य कारणों से प्रशिक्षण की अपेक्षा को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो उस दशा में ऐसी कंपनी को प्रशिक्षणार्थी अधिकारी भर्ती करने की अनुमति है और वह टनभार कर अपनाने वाली कंपनियों के अन्य अर्हता प्राप्त जलयानों अथवा भारतीय ध्वज युक्त कंपनियों के अर्हता प्राप्त जलयानों अथवा विदेशी ध्वज युक्त कंपनियों, जिसके कर्मी भर्ती करने वाले एजेंट ऐसी कंपनियों के साथ प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था का क्रारार करके नौवहन-महानिदेशक के पास पंजीकृत हों, के अर्हता प्राप्त जलयानों पर उपर्युक्त खंड 2 (क) के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगी। ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए सभी भुगतान ऐसी व्यवस्था को प्रायोजित करने वाली टनभार कर चुनने वाली कंपनी को पूर्णरूपेण वहन करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था के लागत का कोई भी भाग प्रशिक्षणार्थी अधिकारी से नहीं वसूला जाना चाहिए।

(ग) जब एक टनभार कर चुनने वाली कंपनी उपर्युक्त खंड 2(ख) के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण की अपेक्षा पूरा कर रही है तो ऐसी न्यूनतम अपेक्षा को केवल उस कंपनी द्वारा पूरा किया जाना माना जाएगा जिसके प्रशिक्षणार्थी अधिकारी जहाज पर प्रशिक्षण के लिए तैनात किए गए हों और न कि उस कंपनी द्वारा जिसके जलयान हैं अथवा जो प्रचालन कर रही है।

3. समुद्र में चल रहे जहाज पर ऐसे सभी प्रशिक्षणार्थी सामान्य जहाज के पूरक के अतिरिक्त होंगे। समुद्र में चल रहे किसी अर्हकारी जहाज पर किसी भी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी का, नौवहन-महानिदेशक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सुरक्षा-जन-प्रबंध-दस्तावेज से संबंधित अपेक्षाएँ निश्चित करने के प्रयोजन से शुमार नहीं किया जाएगा।

4. टनभार कर चुनने वाली कंपनी द्वारा उपर्युक्त न्यास को भुगतान किए जाने योग्य प्रशासनिक लागत तथा टनभार कर चुनने वाली कंपनी द्वारा प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को भुगतान किए जाने योग्य वृत्तिका की धनराशि, नौवहन-महानिदेशक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

5. खंड (4) के अनुसार, टनभार-कर चुनने वाली कंपनी द्वारा किसी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी के संबंध में उपर्युक्त न्यास को भुगतान की जाने वाली प्रशासनिक लागत छ: (6) माह के लिए अग्रिम रूप से अदा की जाएगी।

6. उपर्युक्त न्यास की निधि, नौवहन-महानिदेशक द्वारा क्रायम किए जाने वाले टनभार-कर-प्रकोष्ठ (सैल) से संबंधित सभी प्रशासनिक व्यय वहन करने तथा भारतीय नाविक अधिकारियों के प्रशिक्षण और नियोजन के संवर्धन हेतु प्रयुक्त की जा सकेगी ।

7. टनभार-कर चुनने वाली कंपनी के साथ जहाज पर प्रशिक्षण पूरा करने और निपुणता का प्रमाण-पत्र सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर प्रशिक्षणार्थी अधिकारी उक्त टनभार-कर चुनने वाली कंपनी को अपनी प्रथम तीन वर्ष (छट्टी की अवधि घटाकर)की सेवा की पेशकश कर अनुग्रहीत करेगा, यदि टनभार-कर चुनने वाली कंपनी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी की 3 वर्षों की सेवा लेने की इच्छुक है तथा बशर्ते कि उक्त टनभार-कर चुनने वाली कंपनी तैयार हो और उस स्तर के कंपनी के अन्य अधिकारियों पर लागू सामान्य निबंधन और शर्तों पर अनुच्छेद के अंतर्गत उक्त प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को नियोजित करने को तैयार और इच्छुक हो । टनभार-कर चुनने वाली कंपनी द्वारा प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को दिए जा रहे प्रशिक्षण की सुविधा के मद्देनजर, प्रशिक्षणार्थी अधिकारी टनभार-कर चुनने वाली कंपनी को प्रशिक्षण के लिए स्वीकार किए जाने से पूर्व एक वचन देगा कि वह, प्रशिक्षणार्थी अधिकारी, उसे दिए गए निपुणता प्रमाण-पत्र के द्वारा किसी अन्य नौवहन कंपनी में नौकरी नहीं करेगा जब तक कि वह रोजगार के लिए टनभार-कर चुनने वाली कंपनी से पेशकश स्वीकार नहीं करता, तथापि, बशर्ते कि यदि टनभार-कर चुनने वाली कंपनी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी के निपुणता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और टनभार-कर चुनने वाली कंपनी को रिपोर्ट करने के एक माह के भीतर नियुक्ति की पेशकश नहीं करती है, तब यह समझा जाएगा कि प्रशिक्षणार्थी अधिकारी टनभार-कर चुनने वाली कंपनी में नौकरी करने के अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो गया है और किसी अन्य नौवहन कंपनी में नौकरी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा । तथापि, टनभार-कर चुनने वाली कंपनी भारतीय राष्ट्रीय पोत-मालिक -संघ और नौवहन महानिदेशक को प्रशिक्षण पूरा होने के 15 दिनों के भीतर सूचित करेगी, यह, वह प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को उसके निपुणता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर उसे नौकरी नहीं देती है । ऐसे मामले में प्रशिक्षणार्थी अधिकारी नौवहन कंपनियों से प्राप्त पेशकश को चुन सकता है । नौवहन महानिदेशक ऐसे प्रशिक्षणार्थियों अधिकारियों, जिन्हें टनभार-कर चुनने वाली कंपनी ने नौकरी की ऑफर नहीं किया है और ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को नियोजित करने को सुकर बनाने के लिए एक सूची तैयार करेगा । नौवहन महानिदेशक इस संबंध में समन्वय करेगा और आगे निर्देश जारी करेगा ।

8. निम्नलिखित अवधियाँ उस अवधि के रूप में मानी जाएँगी जिसके दौरान टनभार-कर चुनने वाली कंपनी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

- (i) वह अवधि, जब कोई प्रशिक्षणार्थी अधिकारी, समुद्र में चल रहे किसी आर्हकारी जहाज में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने में विलम्ब हो जाने के कारण अथवा टनभार-कर चुनने वाली कंपनी के नियंत्रण से परे, किसी भी अन्य कारण से विलम्ब हो जाने पर अनुपस्थित हो, जबकि ऐसे विलम्ब के बारे में संबंधित कंपनी द्वारा नौवहन-महानिदेशक को सूचित कर दिया गया हो ।

(ii) जिस मामले में प्रशिक्षण के अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो जाने के सिवाय, किसी अन्य कारण से प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाए तो उस मामले में प्रशिक्षण समाप्त कर दिए जाने की तारीख से भारत में आने वाले अगले पत्तन पर किसी दूसरे प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को प्रतिनियुक्त किए जाने की तारीख के बीच की अवधि, बशर्ते कि टनभार-कर चुनने वाली संबंधित कंपनी ने ऐसा प्रशिक्षण समाप्त किए जाने के 30 दिन के भीतर उसके बारे में नौवहन-महानिदेशक को सूचित कर दिया हो ।

9. (i) टनभार-कर चुनने वाली कंपनी, प्रशिक्षण आरंभ किए जाने के 30 दिन के भीतर नौवहन-महानिदेशक को प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी के संबंध में प्रशिक्षण की अनुसूचित अवधि और उस अर्हकारी जहाज़/उन अर्हकारी जहाज़ों के बारे में सूचित कर देगी, जिस/जिन पर उसे रखा जाएगा और वह उपर्युक्त के संबंध में हुआ कोई बदलाव, 15 दिन के भीतर नौवहन-महानिदेशक को सूचित कर देगी ।

(ii) टनभार-कर चुनने वाली कंपनी, प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर नौवहन-महानिदेशक को प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि और अर्हकारी जहाज़/उन अर्हकारी जहाज़ों के बारे में सूचित कर देगी, जिस/जिन पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को तैनात किया गया था ।

10. टनभार-कर चुनने वाली कंपनी, वित्त वर्ष समाप्त होने के 45 दिन के भीतर, निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हुए नौवहन-महानिदेशक को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगी-

(क) खंड (1) के बारे में स्पष्टीकरण (ग) के अनुसार, वित्तीय वर्ष विशेष से संबंधित प्रशिक्षण से जुड़ी अपनी न्यूनतम अपेक्षा का परिकलन

(ख) उस अवधि का ब्यौरा जिसके दौरान वास्तव में प्रशिक्षण सुलभ करवाया गया और उसके साथ प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी के संबंध में प्रशिक्षण से संबंधित कार्य के दिनों से संबंधित जानकारी का सारांश ;

(ग) वह अवधि, जिसे खण्ड 8 के अनुसार उस अवधि के रूप में माना गया जिसके दौरान प्रशिक्षण सुलभ करवाया गया;

(घ) प्रशिक्षण से जुड़ी अपनी न्यूनतम अपेक्षा पूरी करने में रही कमी यदि कोई हो; और

(ङ.) खण्ड 12 (i) के अनुसार, अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में आगे लायी जाने वाली कमी यदि कोई हो;

(च) वह कमी जिसके संबंध में खण्ड 12 (ii)/ खण्ड 13 के अनुसार भुगतान किया जाना हो ।

11. (i) जिस मामले में नौवहन-महानिदेशक खण्ड 10 के अनुसार वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत ब्यौरे से संतुष्ट नहीं हों तो वह उस मामले में टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी से यह अपेक्षा करते हुए उसे एक नोटिस देंगे कि वह उसमें विनिर्दिष्ट किसी ब्यौरे को ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत कर दे जो 30 दिन से कम नहीं हो और

60 दिन से अधिक नहीं हो तथा वह टनभार-कर चुनने वाली ऐसी कम्पनी को उसकी सुनवाई किए जाने का एक अवसर देंगे। फिर भी, इस बारे में नौवहन-महानिदेशालय को कम्पनियों द्वारा गलत रिपोर्ट भेजे जाने पर नौवहन-महानिदेशालय को ऐसी कम्पनियों द्वारा भेजी गई ऐसी विवरणियों के मामले को फिर से देखने और उसकी फिर से छान-बीन करने और ऐसी आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जो उचित समझी जाए।

(ii) टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के बारे में सुनवाई करने और उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण पर विचार करने के बाद, नौवहन-महानिदेशालय टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा प्रशिक्षण से जुड़ी अपेक्षाओं का निर्वाह किए जाने की जाँच-पड़ताल करेंगे और यह दर्शाते हुए एक प्रमाण-पत्र जारी करेंगे कि संबंधित वित्तीय वर्ष के संबंध में टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित अपेक्षाओं का निर्वाह किया गया है या नहीं तथा प्रशिक्षण से संबंधित अपेक्षाओं का निर्वाह नहीं किए जाने की स्थिति में वह उपर्युक्त प्रमाण-पत्र में प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम अपेक्षा का निर्वाह किए जाने में रही अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में आगे ले जायी जाने वाली कमी के दिनों की संख्या और ऐसी कमी के दिनों की संख्या दर्शाएंगे जिनके संबंध में खण्ड 12/ खंड (13) के अनुसार अतिरिक्त भुगतान किया जाना होगा।

12. (i) टनभार-कर चुनने वाली किसी कम्पनी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम अपेक्षा का निर्वाह किए जाने में, न्यूनतम अपेक्षा के पच्चीस प्रतिशत तक रही किसी कमी के मामले में ऐसी कमी के दिनों की संख्या अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में आगे ले जायी जाएगी।

(ii) टनभार-कर चुनने वाली किसी कम्पनी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम अपेक्षा का निर्वाह किए जाने में न्यूनतम अपेक्षा के पच्चीस प्रतिशत से अधिक रही कमी के मामले में वह टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी, उपर्युक्त न्यास को प्रशिक्षण से संबंधित दायित्व के निर्वाह के स्थान पर नौवहन-महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि हर्जाने के रूप में अदा करेगी।

(iii) टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी, उप-नियम (ii) के अनुसार, उपर्युक्त आदेश मिलने की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद के ठीक अगले दिन से शुरू होने वाली और ऐसे दंड का भुगतान किए जाने के दिन समाप्त होने वाली अवधि में, प्रत्येक माह अथवा उपर्युक्त अवधि में शामिल माह के हिस्से के संबंध में एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने की दायी होगी।

स्पष्टीकरण - इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रयोजन से, प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम अपेक्षा का निर्वाह किए जाने में पहले के किन्हीं वित्तीय वर्षों से आगे लायी गयी कमी पर प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम अपेक्षा के पच्चीस प्रतिशत का परिकलन करने की दृष्टि से विचार नहीं किया जाएगा।

13. टनभार-कर चुनने वाली किसी कम्पनी द्वारा अपने ही जलयानों की किसी किस्म विशेष अथवा अपने व्यापार के पैटर्न या टनभार-कर चुनने वाली अन्य कंपनियों/भारतीय कंपनियों/विदेशी कंपनियों, जिनके

संघालक एजेंट, खण्ड 2(ख) के अनुसार, नौवहन-महानिदेशालय में पंजीकृत हैं, मैं प्रशिक्षण की व्यवस्था करके, प्रशिक्षण की अपेक्षा का निर्वाह नहीं किए जा सकने की स्थिति है तो ऐसी टनभार-कर कम्पनी को उपर्युक्त न्यास को प्रशिक्षण के स्थान पर न्यास को हर्जाना दिए जाने का विकल्प चुनने दिया जाए और नौवहन-महानिदेशालय, प्रत्येक मामले में योग्यता के आधार पर टनभार-कर चुनने वाली कंपनी को न्यूनतम प्रशिक्षण आवश्यकता को पूरा करने से छूट दे सकता है तथा उन्हें नौवहन महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित हर्जाना दिए जाने की अनुमति दे सकता है।

14. इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रशिक्षण से संबंधित अपेक्षाएँ 01.04.2007 से लागू होंगी।

15. बचाव खण्ड-

- क) टनभार-कर चुनने वाली कंपनियों द्वारा रखे गए प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों के लिए जलयानों पर प्रशिक्षण को दिनांक 30.12.2004 की पोत-परिवहन-मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या का० आ० 1436 (आ०) के संगत प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किए जाना जारी रहेगा।
- ख) टनभार-कर चुनने वाली कंपनियों द्वारा रखे गए प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों के लिए जलयानों पर प्रशिक्षण के लिए उनको 1.4.2007 के बाद उनकी प्रशिक्षण अवधि के लिए प्रशिक्षण शुल्क अदा किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

16. नौवहन-महानिदेशक, टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी को कम से कम 10 दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, यह सत्यापित करने की दृष्टि से टनभार-कर चुनने वाली ऐसी कम्पनी के अभिलेखों की जाँच-पड़ताल कर सकते हैं कि उसके द्वारा वार्षिक विवरणी में दी गई जानकारी सही है या नहीं। टनभार-कर चुनने वाली कम्पनी अपने अभिलेखों और प्रलेखन की जाँच-पड़ताल किए जा सकने और उसे सुकर बनाए जाने की दृष्टि से उपयुक्त प्रणाली की व्यवस्था करेगी।

टिप्पणी: नौवहन - महानिदेशक, विभिन्न प्रपत्रों और टनभार-कर चुनने वाली कम्पनियों द्वारा प्रशिक्षण से जुड़ी न्यूनतम अपेक्षाओं का निर्वाह किए जाने की व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने सहित अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में आगे अलग से और परिपत्र/अनुदेश अधिसूचित करेंगे।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Shipping)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 2007

S.O. 2132(E).—In pursuance of Section 115VU of the Income Tax Act, 1961, the Central Government had earlier notified vide S.O.No.1436(E) dated 30.12.2004 the guidelines for providing training by Shipping Companies opting for Tonnage Tax scheme under Chapter XII-G of the Income Tax Act, 1961. The Central Government hereby notified following amended guidelines.

1. A tonnage tax company shall have trainee officers on board all or any of its Qualifying Ships and shall ensure that the aggregate of training man-days on all Qualifying Ships in a financial year is not less than the minimum training requirement.

Explanation: For the purposes of these Guidelines

(a) A ‘trainee officer’ means a cadet passing out of any DGS approved pre-sea training course and possessing the requisite qualifications specified under he Manual on Maritime Education & Training Assessment (META) published by the Director General of Shipping and/or as per guidelines prescribed by the Director General of Shipping, from time to time, who joins a ship as a ‘trainee officer’.

(b) The ‘Trust’ means the ‘Maritime Training Trust’ settled by the Directorate General of Shipping in consultation with INSA.

(c) The ‘minimum training requirement’ for a financial year shall be:

(i) In case of ship owned or chartered-in by the tonnage tax company, (other than space or slot charters), the number of man-days shall be equivalent to the number of days for which such ships are operated by the tonnage tax company during the financial year multiplied by the number of trainee-officers required on such ships based on one and half (1.5) trainee officer for every then (10) complement as per the Minimum Safe Manning Document or pro rata thereof.

(ii) In case of space charters or slot charters, the number of man-days to be calculated by dividing the Net Tonnage of slot/space charters of the tonnage tax company by the Net Tonnage Factor and multiplying the result by number of days for which such ships are operated by the tonnage tax company during the financial year and shall include any shortfall of the immediately preceding financial year brought forward in accordance with clause 12.

Explanation 1: For the purpose of this clause, the Net Tonnage of slot/space charters shall be Net Tonnage as calculated under the notification issued in the official gazette vide Explanation to section 115 VG of the Income Tax Act, 1961,

Explanation 2: The 'Net Tonnage Factor' shall be the factor notified by the Director General of Shipping for each financial year calculated as the aggregate Net Tonnage of all qualifying ships registered under the Merchant Shipping Act, 1958 at the end of the preceding financial year divided by the total number of such ships at the end of the preceding financial year and shall be notified by the Director General of Shipping within 60 days from the beginning of each financial year.

(d) 'Indian National Shipowner.s' Association means the association of Indian ship-owners registered under section 25 of the Companies Act, 1956.'

(e) 'Financial Year' means the period beginning on April 1 and ending on March 31.

2. (a) A tonnage tax company shall recruit trainee officers on board all or any of its qualifying ships from their own resources as a trainee-officer and shall provide the training in accordance with the Manual on Maritime Education & Training Assessment (META) and / or as per training guidelines prescribed by the Director General of Shipping, from time to time.

(b) In the event a tonnage tax company is not in -a position to meet the training requirement by virtue of the type of vessels it owns or its trading pattern or for other reasons to be specified and approved by the Director General of Shipping, such a company is permitted to recruit trainee officers and shall provide training as per clause 2(a) above in other qualifying vessels of tonnage tax opted companies or in qualifying vessels of Indian flag companies or in qualifying vessels of foreign flag companies whose manning agents are registered with the DGS by having contractual arrangements for training trainee officers with such companies. All payments towards such training arrangements should be fully borne by the tonnage tax company sponsoring such arrangements and no part of the cost of such arrangements should be recovered from the trainee officer.

(c) When a tonnage tax company is meeting the minimum training requirement as per clause 2(b) above, such minimum training requirement would be deemed to be met by only the company whose trainee officers have been so placed on board for training and not for the company by whom the vessel is owned or operated.

3. All such trainee officers on board shall be in addition to the normal ship's complement. Any trainee officer on the board of a Qualifying Ship shall not be taken into account for the purpose of determining the minimum safe manning requirements prescribed by the Director General of Shipping.

4. The amount of administrative cost payable by the tonnage tax company to the Trust and stipend payable by the tonnage tax company to the trainee-officer shall be prescribed by the Director General of Shipping, from time to time.

5. The administrative cost payable by the tonnage tax company to the Trust under clause (4) shall be paid in advance for six (6) months.

6. The Trust funds may be used for meeting all the administrative expenses relating to the Tonnage Tax cell to be created by the Director General of Shipping and for the promotion of training and employment of Indian seafaring officers.

7. On completion of on-board training with a tonnage tax company and successful acquisition of a Certificate of Competency, the trainee officer shall be obliged to offer his first three years of service (after deducting leave periods) to the said tonnage tax company, if the tonnage tax company is desirous of availing of the 3years' service from the trainee officer and provided the said tonnage tax company is ready and willing to employ the said trainee officer under articles on usual terms and conditions as are applicable to the other officers of the company at that level. In consideration of the facility of training offered by the tonnage tax company to the trainee officers, the trainee officer shall submit an undertaking to the tonnage tax company, before being accepted for training, to the effect that he, the trainee officer, shall not serve with any other shipping company on the strength of the Certificate of Competency awarded to him, until he accepts the offer of the tonnage tax company for employment, provided, however, that if the tonnage tax company does not make an offer of appointment within one month of the trainee officer acquiring his Certificate of Competency and reporting to the tonnage tax company, the trainee officer will be deemed to have been released of all his obligations to serve the tonnage tax company, and would be free to seek jobs with any other shipping company. However, the tonnage tax company will inform Indian National Shipowners' Association and Directorate General of Shipping within fifteen days of completion of training if it is not offering the job to the trainee on his acquiring Certificate of Competency. In such case trainee officer may choose the offer received from other Shipping Companies. DG(Shipping) will maintain a list of such trainee officers who are not offered job by the tonnage tax company and facilitate placement of such trainee officers. DG(Shipping) will coordinate and issue further instructions in this regard.

8. The following periods shall be deemed as the period during which training is imparted by the tonnage tax company –

- (i) The period for which a trainee officer is absent on the board of a Qualifying Ship due to delay in reporting by the trainee-officer or a delay for any reason beyond the control of the tonnage tax company, where such delay has been intimated by the company to the Director General of Shipping.
- (ii) Where the training is terminated due to any reason other than the scheduled completion of the training, the period between such termination and deputation of another trainee officer at the next port of call in India provided the tonnage tax company has given notice to the Director General of Shipping within 30 days of such termination.

9. (i) The tonnage tax company shall intimate the Director General of Shipping about the scheduled period of training in respect of each of the trainee officers and the Qualifying Ship(s) on which he would be deployed, within 30 days of the start of training and any change therein, within fifteen (15) days.

(ii) The tonnage tax company shall intimate the Director General of Shipping about the actual period of training as well as the Qualifying Ship(s) on which each trainee officer was deployed within 30 days of the date of completion of training.

10. The tonnage tax company shall furnish an annual return to the Director General of Shipping within 45 days of the end of the financial year, providing the following details-

- (a) The calculation of its minimum training requirement for the financial year in accordance with Explanation (c) to clause (1) ;

(b) The period for which it has actually imparted training supported by a summary of the man-days of training with respect of each of the trainee officer;

(c) The period for which it is deemed as imparting the training under clause 8; .

(d) The shortfall, if any, in meeting its minimum training requirement, and

(e) The shortfall to be carried-forwarded, if any, under 12(i) to the subsequent financial year.

(f) The shortfall for which payment has to be made under clause 12(ii)/clause 13.

11 (i) Where the Director General of Shipping is not satisfied with the details submitted in the annual return in accordance with clause 10, he shall serve on the tonnage tax company a notice requiring it to produce within such time, not being less than 30 days and not more than 60 days, any particulars specified therein and shall provide an opportunity of hearing to the tonnage tax company. However, in case of any mis-reporting by companies on this account Directorate General of Shipping shall have the right to reopen and reinvestigate the case and take necessary action as deemed fit.

(ii) After hearing such evidence and after taking into account such particulars as the tonnage tax company may produce, the Director General of Shipping shall determine the compliance by the tonnage tax company of the training requirements and shall issue a certificate stating whether or not the tonnage tax company has complied with the training requirements in respect of the relevant financial year and in case of non-compliance, specifying the number of days of shortfall in meeting the minimum training requirement to be carried forward to the subsequent financial year and the number of days of shortfall in relation to which additional payment may be payable in accordance with clause (12)/clause (13).

12 (i) In case of a shortfall in meeting the minimum training requirement by a tonnage tax company for any financial year is upto twenty five percent of the minimum training requirement, the number of days of such shortfall shall be carried-forward to the subsequent financial year.

(ii) In case of a shortfall in meeting the minimum training requirement by a tonnage tax company exceeding twenty five percent of the minimum training requirement for any financial year, the tonnage tax company shall pay to the Trust penalty by way of an amount as prescribed by the Director General of Shipping from time to time in lieu of the obligation for training.

(iii) The tonnage tax company shall be liable to pay simple interest at one percent for every month or part of a month comprised in the period commencing from the day immediately following the expiry of 30 days from the date of receipt of the order under sub- rule (ii) and ending with the day on which such penalty payment is made.

Explanation - For the purpose of these Guidelines, any shortfall in meeting the minimum training requirements brought forward from any preceding financial years shall not be considered for calculating more than twenty five percent of the minimum training requirement for the year.

13. In the event that the tonnage tax company is not in a position to meet any training requirement by virtue of the type of vessels it owns or its trading pattern or by arranging training in qualifying vessels of other tonnage tax companies / Indian Companies / foreign companies whose manning agents are registered with the DGS as per clause 2(b), such tonnage tax company may opt to pay penalty to the Trust in lieu of training and the Directorate General of Shipping may on the merit of each case grant exemption to the Tonnage Tax Company from meeting the minimum training requirement and permit it to pay penalty as prescribed by the Director General of Shipping from time to time.

14. Training requirements under these guidelines shall be applicable from 01.04.2007.

15. Saving Clause -

- a) The trainee officers engaged by the tonnage tax companies for on board training would continue to be regulated by the relevant provisions Ministry of Shipping Gazette Notification S.O.1436(E) dated 30.12.2004.
- b) The trainee officers engaged by the tonnage tax companies for on board training would not be required to pay the training fees for their period of training after 1.4.2007.

16. The Director General of Shipping after giving notice in writing of not less than ten days to the tonnage tax company, can examine the records of such tonnage tax company to verify that the information given in relation to the annual return is correct. The tonnage tax company shall make provision for a suitable system to enable and to facilitate the checking of its records and documentation.

Note: The Director General of Shipping will notify the further circular/instructions on other relating aspects including various forms and describing the system for administering the minimum training requirements by tonnage tax companies separately.

[F. No. SD-11018/12/2002-MD]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.